

रजिस्टर्ड नं० एन० ३३/एस० एम०/१३-१४/७५.



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, शुक्रवार, ३१ मार्च, १९७५/१० चैत्र, १९१७

---

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रधिसूचना

शिमला-४/ ३१ मार्च, १९७५

संख्या १-२०/७५-वि०स०.—नियोजनालय (चिकित्सकीय प्रशिक्षण) हिमाचल प्रदेश (मंशोधन)  
विधेयक १९७५ (१९७५ का विधेयक संख्यांक ४) जो आज दिनांक ३१ मार्च, १९७५ को हिमाचल प्रदेश विधान सभा

में पुरःस्थापित हो गया है की एक प्रति हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत सर्व-साधारण का सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में प्रवृत्त करने हेतु प्रेषित की जाती है ।

के० एल० वर्मा,  
सचिव ।

1995 का विधेयक संख्यांक 4.

## नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) हिमाचल प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 1995

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 31) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) हिमाचल प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 1995 है।

संक्षिप्त  
नाम।

1959 का  
31.

2. नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में—

धारा 3 का  
संशोधन।

- (i) उप-धारा (1) में, खण्ड (घ) का लोप किया जाएगा; और
- (ii) उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में "भाट हुए" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपये" शब्द रखे जाएंगे।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में, उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

धारा 4 का  
संशोधन।

"(4) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन किसी रिक्ति की अधिसूचना पर नियोजनालय जिसे रिक्ति अधिसूचित की जाती है, उपयुक्त अभ्यर्थियों को समर्थित करेगा और नियोजक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नियोजनालय द्वारा समर्थित अभ्यर्थियों में से किसी व्यक्ति को भर्ती करेगा।

(5) जहां नियोजनालय उपयुक्त अभ्यर्थी का समर्थन करने में असफल रहता है या नियोजक उप-धारा (4) के अधीन नियोजनालय द्वारा समर्थित अभ्यर्थियों में से रिक्ति को भरने में असमर्थ रहता है वहां नियोजक, ऐसे प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से जैसा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी यह अधिरूपित करना चाहे, ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भर्ती करेगा।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

धारा 7 का  
संशोधन।

- (i) उप-धारा (1) में, "पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा और हर पश्चात्तर्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा और हर पश्चात्तर्वर्ती अपराध के लिए साधारण कारावास से जो छः मास तक का, हो सकेगा और जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा से," शब्द रखे जाएंगे; और

- (ii) उप-धारा (2) में, "दो सौ पचास रुपये" और "पांच सौ" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "दो हजार पांच सौ" और "पांच हजार" शब्द रखे जाएंगे।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

नियोजनालयों की भूमिका सरकारी और अर्धसरकारी सैक्टर तक, वह भी सेवाओं के रजिस्ट्रीकरण और प्रेषण की व्यवस्था उपलब्ध करने तक ही परिसीमित रही है। अधिकांश प्राइवेट सैक्टर जो मुख्य नियोजक रहा है, छोड़ दिया गया है। नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 की धारा 4 के अधीन प्राइवेट सैक्टर द्वारा रिक्तियों को अधिसूचित करने के लिए, उन्हें नियोजनालयों के अन्तर्गत लाने के लिए कतिपय प्रयास किये गए हैं, जो अपर्याप्त हैं। अधिनियम की धारा 4(4) के अधीन यह स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम नियोजकों पर किसी रिक्ति को, केवल उस आधार पर कि रिक्ति अधिसूचित कर दी गई है, नियोजनालयों के माध्यम से किसी व्यक्ति को भर्ती करने के लिए, बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है। तथापि केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा सभी सरकारी नियोजकों द्वारा नियोजनालयों के माध्यम से ही भर्ती करने के लिए कार्यकारी और प्रशासनिक आदेश किए गये हैं, क्योंकि केवल नियोजनालयों द्वारा भर्ती किया जाना और उनके द्वारा की गई नियोजन सेवा एक मुख्य भूमिका रही है। किन्तु यद्यपि नियोजनालय सेवा के संस्थापन क्रियाकलाप को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। फिर भी नियोजनालय सेवा का प्राइवेट सैक्टर सेवा में घुस पैठ करना नाममात्र रहा है। वास्तव में देखा जाए तो नियोजनालय केवल एक रजिस्ट्रीकरण कक्ष बन कर ही रह गया है।

नियोजनालयों के सक्रिय रजिस्ट्रारों में बेरोजगार लोगों का रजिस्ट्रीकरण अत्यधिक है और उनमें से कुछ को ही नौकरी के अवसर प्राप्त होते हैं, बेरोजगारों को पर्याप्त नौकरी के अवसर प्राप्त न होने पर, नियोजनालयों के प्रति जनता का विश्वास कम होता जा रहा है और नौकरी के लिए साक्षात्कार का कई वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहने पर नौकरी की तलाश करने वालों में अमन्तोष और बेचैनी व्यापक रूप में फैल रही है। यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न सरकारी विभागों ने अपने भर्ती बोर्ड स्थापित किए हैं और रिक्तियां उन द्वारा भरी गई हैं और नियोजनालयों को अधिसूचित नहीं की गई है जिस के कारण नियोजनालयों के कार्य में कमी आई है। इसके अतिरिक्त सरकार ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रों को जो पब्लिक सैक्टर के लिए आरक्षित थे, प्राइवेट निगमों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपने से प्राइवेट सैक्टर के क्षेत्र में विस्तार किया है। इससे नियोजनालयों के स्थापन क्रियाकलापों पर भी प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा है। बेरोजगारी समस्या जो एक भयप्रद चेतावनी बनी हुई है उसे सुलझाने के लिए अधिनियम में अन्तर्निहित नीति का पुनर्विलोकन किया जाना अत्यावश्यक हो गया है। जब भर्ती नियोजनालय के माध्यम से की जायेगी तो ईमानदारी, निष्पक्षता, उद्देश्यपूर्ण और सामाजिक न्याय जैसे मिद्वांतों का सेवाओं के प्रेषण में स्वतः ही अनुपालन हो जाएगा। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ और अन्य बनाम हरगोपाल और अन्य ए० आई० आर० 1987 एस० सी० 1227 में अपने निर्णय में यह अधिकृत किया है कि नियोजन के मामले में मनमानी और पक्षपात को दूर करना तथा मानक एकरूपता और क्रमबद्धता लाना आवश्यक है। नियोजनालयों के माध्यम से प्रदान की गई भर्ती की सहायता से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में प्रव्याभूत अधिकार प्रतिबन्धित होने के बजाए विकसित होते हैं। पूर्वाक्त को मध्यनजर रखते हुए, यह उपबन्ध करना आवश्यक हो गया है कि रिक्तियां नियोजनालयों को अधिसूचित की जाएं, किन्तु रिक्तियां नियोजनालयों द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों से ही भरी जानी चाहिए। अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और शास्ति बहुत कम है और अधिक निवारक नहीं है। इसलिए अधिनियम के उपबन्धों को अधिक प्रभावकारी और निवारक बनाने के लिए जुर्माने और शास्तियों की मात्रा का बढ़ाया जाना भी आवश्यक है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

रंगीला राम राव,  
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

31 मार्च, 1995

**विस्तीय आपन**

—शून्य—

—

**प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी आपन**

—शून्य—

## AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 4 of 1995.

## THE EMPLOYMENT EXCHANGES (COMPULSORY NOTIFICATION OF VACANCIES) HIMACHAL PRADESH (AMENDMENT) BILL, 1995

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*to amend the Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959 (Central Act No. 31 of 1959) in its application to the State of Himachal Pradesh.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Himachal Pradesh (Amendment) Act, 1995.

Amendment of section 3.

2. In section 3 of the Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959 (hereinafter called the principal Act)—

31 of 1959

- (i) in sub-section (1), clause (d) shall be deleted ; and
- (ii) in sub-section (2), in clause (b), for the words "sixty rupees", the words "five hundred rupees" shall be substituted.

Amendment of section 4.

3. In section 4 of the principal Act, for sub-section (4), the following shall be substituted, namely:—

"(4) On the notification of a vacancy under sub-section (1) or sub-section (2), the employment exchange, to which vacancy is notified, shall sponsor suitable candidates and the employer shall recruit any person from amongst the candidates sponsored by the employment exchange to fill up such vacancy.

- (5) Where the employment exchange fails to sponsor a suitable candidate or the employer is unable to fill up the vacancy from amongst the candidates sponsored by the employment exchange under sub-section (4), the employer, with the prior approval of such authority as may be authorised by the State Government in this behalf and subject to such conditions as it may like to impose, recruit any other person to fill up such vacancy."

Amendment of section 7.

4. In section 7 of the principal Act,—

- (i) in sub-section (1), for the words "five hundred rupees and for every subsequent offence with fine which may extend to one thousand rupees", the words "five thousand rupees and for every subsequent offence with simple imprisonment which may extend to six months and with fine which may extend to ten thousand rupees" shall be substituted ; and
- (ii) in sub-section (2), for the words "two hundred and fifty" and "five hundred", the words "two thousand and five hundred" and "five thousand" shall respectively be substituted.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The role of employment exchanges has remained confined to the Government and Semi-Government sector, that too in the area of providing registration and referral services. A bulk of the private sector, which is a major employer, is still left out. Some attempts have been made to cover private sector also by requiring them to notify vacancies under section 4 of the Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959 which is hardly adequate. Under section 4 (4) of the Act, it has been clarified that the Act does not impose any obligation upon any employer to recruit any person through the employment exchange to fill any vacancy merely because that vacancy has been notified. However, a host of executive and administrative orders both by the Central and State Governments, enjoining all the Government employers to recruit their man-power only through the employment exchanges has firmly entrenched placement as the key role of the employment service rendered by the employment exchanges. But even though the private sector provides a fertile ground for making considerable inroads to set up the placement activity of employment service, the penetration of employment service into private sector placement is extremely minimal. The employment exchanges have virtually been reduced to mere registration Cells.

A vast reservoir of the un-employed man-power is available on the live registers of employment exchanges, a fraction of whom is currently getting job opportunity. Due to gradual erosion of the placement role of employment exchanges faith of the public is dwindling, and is causing bitter discontent and frustration among the job seekers waiting on live registers for years hoping to get an interview. It is note-worthy that various Government Departments have constituted their own Recruitment Boards which has resulted in colossal erosion of vacancies which could have been notified to employment exchanges. Apart from this, with a view to give boost to modernisation of Indian economy, the Government has expanded the scope of private sector by throwing open those areas to private corporations and multinational companies, that were hitherto reserved for public sector. This has also adversely affected the role of the employment exchanges with regard to their placement activity. To tackle the unemployment problem which has indeed an alarming magnitude, there is currently a prime and pressing need to review the policy embodied in the Act. The principles of fair play impartiality, objectivity and social justice in referral operations are automatically taken care and guarded, when recruitments are channelised through employment exchanges. The apex Court of this country in its judgment *Union of India and others v/s N. Hargopal and others*, AIR 1987 S C 1227 has laid down that in the case of employment, it is necessary to eliminate arbitrariness and favouritism and introduce uniformity of standards and orderliness in the matter of employment. The assistance of recruitment through employment exchanges advances rather than restricts the rights guaranteed by Articles 14 and 16 of the Constitution. In the light of above, it has become necessary to provide that not merely vacancies should be notified to the employment exchanges, but the vacancies should also be filled by candidates sponsored by the employment exchanges. As fines and penalties provided for contravention of the provisions of the Act are very meagre and are not deterrent, it is also necessary to increase the quantum of fines and penalties to make the provisions of the Act more effective and deterrent.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

RANGILA RAM RAO,  
Minister-in-Charge.

## FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-